



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223050
CG-DL-E-12112020-223050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3565]
No. 3565]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4048(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 608(अ.), दिनांक 24 फरवरी, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षाानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

नरगू वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले में मंडी से लगभग 55 किलोमीटर, जोगिंदर नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो विभिन्न स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु को आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिवैज्ञानिक और मनोरंजनात्मक और अनुसंधान एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से काफी महत्वपूर्ण है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 132.37 वर्ग किलोमीटर है;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आर्द्र देवदार वन, 12 सी1 (सी), आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वन 12/सी1(ई), खरसू ओक वन 12/सी2(ए), उप-उष्णकटिबंधीय चीड़ पाइन वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, पश्चिमी हिमालय उप-अल्पाइन देवदारु वन आते हैं। अभयारण्य में महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में देवदार (*केदरुस देवदार*), फर (*अविडिस पिंदरोप*), खरसू (*क्वेरसुस सेमिकारपीफोलीअ*), प्रूनस (*प्ररूनस अवियम*), मापले (*अकेर स्पा*), जुगलान (*जुगलान रेलगिया एल*), रोडोडेंड्रोन (*रोडोडेंड्रोन अरबोरेतम*), केलटीस (*केल्टिस ऑस्ट्रेलिस एल*), फिग (*फिकस पालमेट*), वान (*क्वेरसुस लुकट्रैकोफोरा*), आदि पाए जाती हैं;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव की विशेष विविधता के वास के लिए जाना जाता है। अभयारण्य में मुख्य प्रजातियों में संकटापन्न प्रजातियों जैसे सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), काला भालू (*सेलेनारक्टस थिवेटेनस*), घोराल (*नेमोराएडस गोरल*), सियार (*कैनिस् ऑरियस*), हिमालयन येलो थ्रोटेड मार्टेन (*मार्टेस फ्लाविगुला*), हिमालयन सिवेट (*पगोमा लारवाटा*), फ्लाइंग गिलहरी (*पेटोरिस्टा पेटोरिस्टा*) पाए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फेजेंट की सात प्रजातियों में से चार प्रजातियों का वास है। इसे भारत में हिमालयन क्षेत्र में प्रतिबंधित स्थानिक असुरक्षित प्रजातियों हिमालयी मोनल, के लिए महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा अन्य पक्षी, सफेद क्रेस्टेड कलीज, चूकोर, काला और ग्रे तीतर है। इसके अलावा सरीसृप, सांप, मॉनीटर छिपकली सामान्य रूप से पाए जाते हैं;

और, नरगू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी और कुल्लू जिला के नरगू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0 (शून्य) से 1.00 किलोमीटर तक भिन्न रूप में फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 50.0425 वर्ग किलोमीटर है। धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य के साथ अभयारण्य के अविच्छन्न होने के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। तथापि, नरगू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा चाकरोला थच से आरंभ होती है और घरालीटीनू गलू तक जिला सीमा के साथ धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा का साथ सुझती है।

(2) नरगू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए नरगू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक-IIक** और **अनुलग्नक-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची, मुख्य बिंदुओं पर उनके भू-निर्देशांकों के साथ **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका विभाग;
- (vi) राजस्व विभाग;
- (vii) कृषि;
- (viii) ग्रामीण विकास;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (x) हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (xi) पंचायती राज; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नदी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, वागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत्य नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत्य किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत्य नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत्य होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत्य नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत्य होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुमति नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्साव का निस्सरण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमति किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमति किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुमति नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;

		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	मछली पकड़ना और शिकार करना।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।

		परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे।
23.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्साव का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्साव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्साव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	ट्रेकिंग और शिविर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	फोटोग्राफी वाणिज्यिक।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	वायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना।	बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	धार्मिक ट्रेकिंग।	बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	वन संरक्षक, मंडी और कुल्लू	अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;

(iii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(iv)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वनाधिकारी, मंडी	सदस्य;
(viii)	प्रभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव कुल्लू	सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वनाधिकारी, जोगिन्दरनगर	सदस्य;
(x)	प्रभागीय वनाधिकारी, कुल्लू	सदस्य- सचिव

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के **पैराग्राफ 4** के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/176/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गडकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

सारणी: हिमाचल प्रदेश राज्य में नरगू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर भाग पर प्रस्तावित नहीं है जैसा कि यह धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य के साथ अविच्छिन्न है, तथापि, नरगू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा चकरोला थच से आरंभ होती है और घरालीटीनू गलू तक जिला सीमा के साथ धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 32° 02' 58.042" देशांतर 76° 52' 5.991"

अक्षांश 32° 06' 36.803" देशांतर 76° 58' 49.573".

दक्षिण: सीमा कंडी गलू से आरंभ होकर, कंडी ग्राम के उत्तरी भाग पर मुड़ती है और छोटे नाला के साथ नीचे की ओर जाती है और दूचली नाला सीमा से जुड़कर मटीयाना ग्राम के उत्तरी भाग में मुड़ती है इसके बाद के बरौन नाला तक 1600 मीटर परिरिखा में मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 31° 49' 46.841" देशांतर 77° 04' 54.074"

अक्षांश 31° 48' 35.52" देशांतर 77° 02' 46.257"

पूर्व: सीमा घरालीटीनू गलू से आरंभ होती है, छोटे नाला के साथ नीचे की मुड़ती है, इसके बाद 2800 मीटर परिरिखा के साथ मुड़ती है और सरवरी खाद से जुड़कर छोटे नाला के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद सरवरी खाद के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद पथ सीमा के साथ मुड़ती है, छोटे नाला के ऊपर की ओर मुड़कर सम्लंग ग्राम, तीऔन ग्राम, द्रलीजीग ग्राम, कदीचा ग्राम, समाना ग्राम, सगोचन ग्राम, बाई धरंग ग्राम, कराशींग ग्राम, कशामती ग्राम, तेलंग, दैल ग्राम की पश्चिम सीमा की पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ती है इसके बाद छोटे नाला के साथ ऊपर की ओर मुड़कर और 2600 मीटर परिरिखा मुड़ती है वन सीमा मरींग पी एफ के साथ खोपरी ग्राम, मरगन ग्राम, जोंगा ग्राम की पश्चिमी सीमा के नीचे की ओर मुड़ती है इसके बाद मुलागथाना पी एफ के साथ मुड़कर सीमा बौसू ग्राम, भाखरी ग्राम, पहे ग्राम, सपाका ग्राम के पश्चिमी भाग मुड़ती है; इसके बाद कंडी गलू के खोखान वन्यजीव अभयारण्य सीमा मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 32° 06' 36.803" देशांतर 76° 58' 49.573"

अक्षांश 32° 02' 6.634" देशांतर 76° 59' 42.926"

अक्षांश 31° 54' 18.948" देशांतर 77° 04' 0.646"

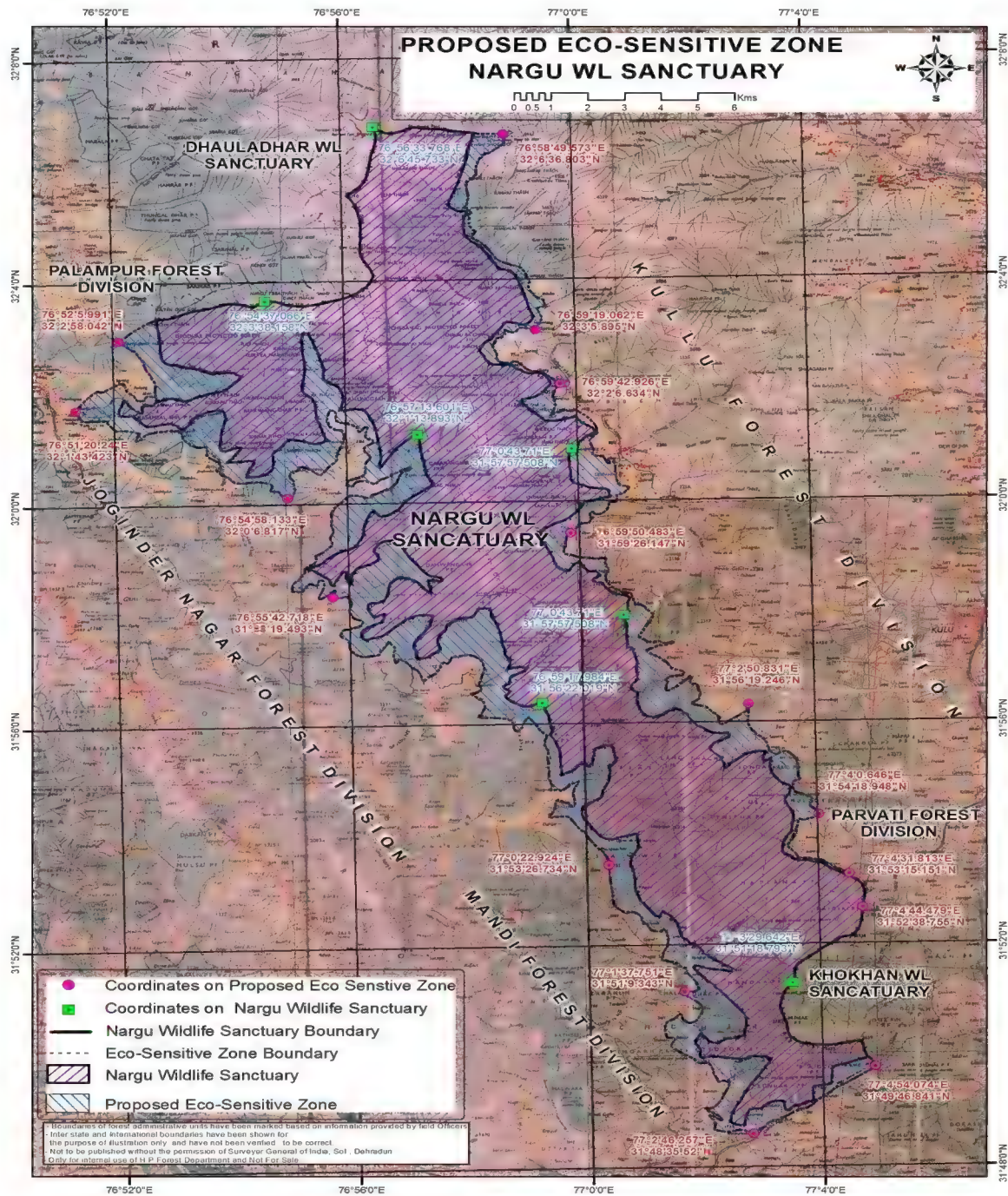
अक्षांश 31° 49' 46.841" देशांतर 77° 04' 54.074"

पश्चिम : सीमा बरौन नाला से आरंभ होकर शनर ग्राम, सेरीग्राम, भरयनू ग्राम, बरारी ग्राम की पूर्वी सीमा के पथ के साथ बरौन ग्राम की पूर्वी सीमा मुड़ती है, छोटे नाला के नीचे की ओर मुड़कर और शेरारा नाला से जुड़ती है और नाला के ऊपर की ओर मुड़कर और गरटनू ग्राम, धरौन ग्राम की उत्तरी सीमा से मुड़ती है और सीमा नाला के ऊपर की ओर दरून ग्राम, शूघा ग्राम के पूर्वी भाग के रिज के साथ पथ- एस ओ आई बेंचमार्क 2453 मीटर के साथ मुड़ती है और सीमा 2600 मीटर परिरिखा मुड़ती है इसके बाद पथ एस.ओ.आई बेंचमार्क 2321 मीटर ग्राम मुड़ती है इसके बाद भडवानी ग्राम, करतंग ग्राम के पश्चिमी भाग छोटे नाला के साथ मुड़ती है और ओलगवर ग्राम के उत्तर भाग पथ के साथ मुड़ती है और दैत ग्राम, दमवन ग्राम के पूर्वी भाग पथ ग्राम मुड़ती है और 2200 मीटर परिरिखा मुड़ती है इसके बाद तेगर ग्राम के पूर्वी भाग है और सीमा नाला के साथ ग्राम पथ के साथ मुड़ती है और तेरंग ग्राम के उत्तरी भाग के 2400 मीटर परिरिखा मुड़ती है इसके बाद ग्राम पथ मुड़ती है और इसके बाद 2740 मीटर परिरिखा के साथ मुड़ती है और इसके बाद लथरन ग्राम के उत्तरी भाग मुड़कर और झाकवन घर नाला से जुड़कर 2200 मीटर परिरिखा मुड़ती है और इसके बाद सीमा बनजसगढ़ ग्राम के पथ के साथ मुड़ती है और इसके बाद बनजसगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा मुड़ती है इसके बाद पथ के साथ मुड़कर और 1720 मीटर परिरिखा मुड़ती है। इसके बाद छोटे नाला के ऊपर की ओर मुड़ती है और सीमा चकरोला थच तक मंडी और कांगडा की जिला सीमा मुड़ती है।

भू-निर्देशांक: अक्षांश 31° 48' 35.52" देशांतर 77° 02' 46.257"
 अक्षांश 31° 53' 26.734" देशांतर 77° 0' 22.924"
 अक्षांश 31° 58' 19.493" देशांतर 76° 55' 42.718"
 अक्षांश 32° 01' 43.423" देशांतर 76° 51' 20.24"
 अक्षांश 32° 02' 58.042" देशांतर 76° 52' 5.991"

अनुलग्नक- IIक

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र





	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)	विवरण(भू-चिन्ह)
उत्तर	76° 52' 5.991" 76° 58' 49.573"	32° 02' 58.042 32° 06' 36.803	धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और जिला सीमा के साथ चकरोलाथच से घरालीटीनू गलू तक
दक्षिण	77° 04' 54.074" 77° 02' 46.257"	31° 49' 46.841" 31° 48' 35.52"	कन्दी गलू, दुल्सी नाला, बरौन नाला तक 1600 मीटर परिरेखा
पूर्व	76° 58' 49.573"	32° 06' 36.803	परिरेखा 2800 मीटर एवं 2600 मीटर, मरीग, मुलगान थाना, इसके बाद कन्दी गलु तक खोखान

	76° 59' 42.926"	32° 02' 6.634	वन्यजीव अभयारण्य के साथ है।
	77° 04' 0.646"	31° 54' 18.948"	
	77° 04' 54.074"	31° 49' 46.841"	
पश्चिम	77° 02' 46.257"	31° 48' 35.52"	वरौन नाला, सेर नाला, भारतीय सर्वेक्षण निर्देशचिन्ह 2453, 2321, परिरेखा 2200, 2400, 27401720 मीटर, इसके बाद चकरोला थच तक मंडी और कंगडा की जिला सीमा के साथ साथ जाती है।
	77° 0' 22.924"	31° 53' 26.734"	
	76° 55' 42.718"	31° 58' 19.493"	
	76° 51' 20.24"	32° 01' 43.423"	
	76° 52' 5.991"	32° 02' 58.042"	

अनुलग्नक-IV

क. भू-निर्देशांकों के साथ नरगू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

प्रभाग	क्र.सं.	ग्राम नाम	अक्षांश	देशांतर
जोगिंदरनगर	1	कशमाल	32° 01' 517"उ	76° 51' 524"पू
	2	तेरांग	32° 58' 648"उ	76° 55' 476"पू
	3	तेगर	31° 58' 964"उ	76° 55' 014"पू
	4	समालांग	31° 58' 648"उ	76° 55' 941"पू
	5	गढगौन	31° 58' 398"उ	76° 55' 984"पू
	6	कुंगरी	31° 56' 981"उ	76° 57' 320"पू
पार्वती		शून्य		
कुल्लू		शून्य		
मंडी	1	कोट	31° 52.245"उ	077° 01.438"पू
	2	पाधर	31° 52.208"उ	077° 01.430"पू
	3	लेहरी	31° 52.003"उ	077° 01.577"पू
	4	कुमाहारदु	31° 51.812"उ	077° 01.370"पू
	5	मंद्रा	31° 52.005"उ	077° 01.577"पू
	6	भरारी	31° 51.660"उ	077° 01.625"पू
	7	बदाउन	31° 49.463"उ	077° 01.769"पू
	8	मथिअना	31° 48.445"उ	077° 02.450"पू
	9	सारंग	31° 48.532"उ	077° 02.469"पू

	10	कुंदाक	31° 49.123"उ	077° 03.038"पू
	11	कंधी	31° 49.688"उ	077° 04.863"पू

ख. नरगू वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	वन के नाम	कम्पार्टमेंटों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
1	2/57 फेती मेल	सी-1,सी-II (भाग)	0.335
2	2/61 मारिग	सी-1-सी-IV(भाग)	0.565
3	मानगढ़ -III	(भाग)	4.900
4	चोपरासा-III	(भाग)	1.750
5	तारापुर-III	(भाग)	3.600
6	महराजा-III	(भाग)	1.10
7	लामबाचाक एवं राजस्व भूमि	(भाग)	3.0050
8	तेरांग एवं रीचुनाल एवं राजस्व भूमि		1.8125
9	दैतनल एवं राजस्व भूमि		2.1350
10	कुंगरी		3.2275
11	वांगन		1.7725
12	खवान एवं राजस्व भूमि		0.9950
13	ग्रामन एवं खारयान		6.8750
14	गरहगांव एवं राजस्व भूमि		3.1975
15	कश्मलशील ग्राम	(भाग)	1.4300
16	सरकारी अपशिष्ट भूमि एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.0600
17	शगनाल	संपूर्ण	0.8097
18	चुनचल	संपूर्ण	0.6070
19	बरा	संपूर्ण	1.1600
20	हिमगढ़ एवं राजस्व भूमि	(भाग)	0.8750
21	बदउन एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.9050
22	हाथीपुर	(भाग)	2.4755
23	हिरवानाल एवं राजस्व भूमि		
24	फुंगान्धार		
25	शगनाल एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.2528

26	चलाउधार	(भाग)	0.8775
27	नया मंदरा एवं राजस्व भूमि	(भाग)	0.7725
28	कंडी एवं राजस्व भूमि	(भाग)	1.5475
		कुल योग	50.0425

अनुलग्नक-V**की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4048(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 608 (E), dated 24th February, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Nargu Wildlife Sanctuary is situated at a distance around 55 kilometres from Mandi, 30 kilometres from Joginder nagar in Mandi and Kullu district of Himachal Pradesh which provides home to a variety of endemic flora and fauna. The Sanctuary has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research or educational perspective. The total area of the Sanctuary is 132.37 square kilometers;

AND WHEREAS, Nargu Wildlife Sanctuary consists of Moist Deodar Forests, 12 C1 (c), Moist Temperate Deciduous Forests 12/C1(e), Kharsu Oak Forests 12/C2(a), Sub-tropical Chir Pine Forest, Western Mixed Coniferous Forests, Western Himalaya Sub-alpine Fir Forest. Important tree species available in the Sanctuary are deodar (*Cedrus deodara*), fir (*Abies pindrop*), kharsu (*Quercus semicarpifolia*), prunus (*Prunus avium*), maple (*Acer spp*), juglan (*Juglan regia* L), rhododendron (*Rhododendron arboretum*), celtis (*Celtis australis* L), fig (*Ficus palmate*), ban (*Quercus leucutrichophora*), etc;

AND WHEREAS, Nargu Wildlife Sanctuary is known to harbor an exceptional varieties of wildlife. The main species found in the Sanctuary are threatened species like, common leopard (*Panthera pardus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), black bear (*Selenarctus thibetanus*), ghoral (*Nemorhaeadus goral*), jackal (*Canis aureus*), Himalayan yellow throated marten (*Martes flavigula*), Himalayan civet (*Pagoma larvata*), flying squirrel (*Petaurista petaurista*). It is habitat of four species of pheasants out of seven species found in Himachal Pradesh. It has been recognized as important bird area for Himalayan monal, endemic vulnerable species restricted to Himalayan region in India. Among other birds, white crested kalij, chukor, black and grey partridge. Among reptiles snakes, monitor lizard are of common occurrence;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nargu Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zones;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.00 kilometres around the boundary of Nargu Wildlife Sanctuary, in Mandi and Kullu district in the State of Himachal Pradesh as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 (zero) to 1.00 kilometres and the area of the Eco-sensitive Zone is 50.0425 square kilometres. *Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to continuation of the Sanctuary with Dhouladhar Wildlife Sanctuary. However, the boundary of Nargu Wildlife Sanctuary start from Chakrola Thach and moves along South West boundary of Dhouladhar Wildlife Sanctuary along district boundary upto Ghralitinu Galu.*
 - (2) The boundary description and geo-coordinates of Nargu Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Nargu Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Eco-Sensitive Zone of Nargu Wildlife Sanctuary are given in **Annexure-III**.
 - (5) The list of revenue villages inside the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo coordinates at prominent points are given in **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal Department;
 - (vi) Revenue Department;

- (vii) Agriculture;
 - (viii) Rural Development;
 - (ix) Irrigation and Flood Control;
 - (x) Himachal State Pollution Control Board;
 - (xi) Panchayati Raj; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3 Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

1. new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

- (6) **Noise pollution.**— Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

- (7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.**— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

- (9) **Solid wastes.**— Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.**(12) Construction and demolition waste management.**— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.**(13) E-waste.**— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.**(14) Vehicular traffic.**— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.**(15) Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.**(16) Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-**TABLE**

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman</p>

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
10.	Fishing and Hunting.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Tracking and camping.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Photography commercial.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
43.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Shall be promoted.
44.	Religious tracking.	Shall be promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Conservator of Forests, Mandi and Kullu	Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Regional Executive Engineer of State pollution Control Board	Member;
(iv)	Senior Town Planner of the area.	Member;
(v)	One expert in Ecology and environment to be nominated by State	Member;
(vi)	One expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Mandi	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Wildlife Kullu	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Jogindernagar	Member;
(x)	Divisional Forest Officer, Kullu	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/176/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**TABLE: BOUNDARY DESCRIPTION OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE HIMACHAL PRADESH**

North : Eco-sensitive Zone is not proposed on north side as it is continuous with Dhouladhar Wildlife Sanctuary however, the boundary of Nargu WLS start from Chakrola Thach and moves along south west boundary of Dhouladhar Wildlife Sanctuary along district boundary upto Ghralitnu Galu.

Geo-coordinates: Lat 32° 02' 58.042" Long 76° 52' 5.991"

Lat 32° 06' 36.803" Long 76° 58' 49.573".

South : The boundary start from Kandi Galu moves to northern side of Kandi village and downward with a small nalla and join Dulchi nalla boundary moves northern side of Matiyana village then moves 1600 meters. Contour upto Baraun Nalla.

Geo-coordinates: Lat 31° 49' 46.841" Long 77° 04' 54.074"

Lat 31° 48' 35.52" Long 77° 02' 46.257"

East : The boundary start from Ghralitnu Galu moves downward along small nalla then moves along 2800 meters. Contour and moves downward small nalla join Sarwari khad then moves downward Sarwari khad than moves along path boundary moves upward small nalla moves to western boundary of Smalang village, Tiun village, Drljig village, Kadincha village, Samana village, Sagochag village Baidharang village, Krashing village, Kashamti village, Telang, Dail village then moves upward with small nalla and moves 2600 meters contour moves small nalla downward to western boundary of Khopri village, Margan village, Jonga village along forest boundary Maring PF then Moves to Mulagthana PF the boundary moves western side of Bousu village, Bhakhri village, Pah village Sapaka village then moves Khokhan Wildlife Sanctuary boundary upto Kandi Galu.

Geo-coordinates: Lat 32° 06' 36.803" Long 76° 58' 49.573"

Lat 32° 02' 6.634" Long 76° 59' 42.926"

Lat 31° 54' 18.948" Long 77° 04' 0.646"

Lat 31° 49' 46.841" Long 77° 04' 54.074"

West : The boundary start from Baraun Nalla moves eastern boundary of Baraun village along the path of eastern boundary of Shanar village, Seri village Bharyanu village, Brari village boundary moves down ward a small nalla and join Shera ra nalla and moves upward the nalla and moves the northern boundary of Gartanu village, Gharaun village and boundary moves along path SOI bench mark 2453 meters along ridge of eastern side of Darun village, Shugha village upward with a Nalla and boundary moves 2600 meters. Contour then moves the village path SOI bench mark 2321 meters then moves along small nalla western side of Bhadwani village, Kartang village and moves along path north side of Aolgwar village and moves the village path eastern side of Daint village, Damwan village and moves along 2200 meters. Contour then eastern side of Tegar village and boundary moves along village path along with nalla and then moves 2400 meters contour of northern side of Terang village then moves village path and then moves along 2740 meters. Contour and then moves northern side of Lthran village and moves 2200 meters contour join

Lat 32°02' 58.042" Long 76°52' 5.991"

**PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE
NARGU WL SANCTUARY**

Scale: 0 0.5 1 2 3 4 5 Kms

Legend:

- Coordinates on Proposed Eco Sensitive Zone
- Coordinates on Nargu Wildlife Sanctuary
- Nargu Wildlife Sanctuary Boundary
- Eco-Sensitive Zone Boundary
- Nargu Wildlife Sanctuary
- Proposed Eco-Sensitive Zone

Map Labels:

- DHAULADHAR WL SANCTUARY
- PALAMPUR FOREST DIVISION
- JOGINDER NAGAR FOREST DIVISION
- NARGU WL SANCTUARY
- MANDI FOREST DIVISION
- PARVATI FOREST DIVISION
- KHOKHAN WL SANCTUARY
- TULU FOREST DIVISION

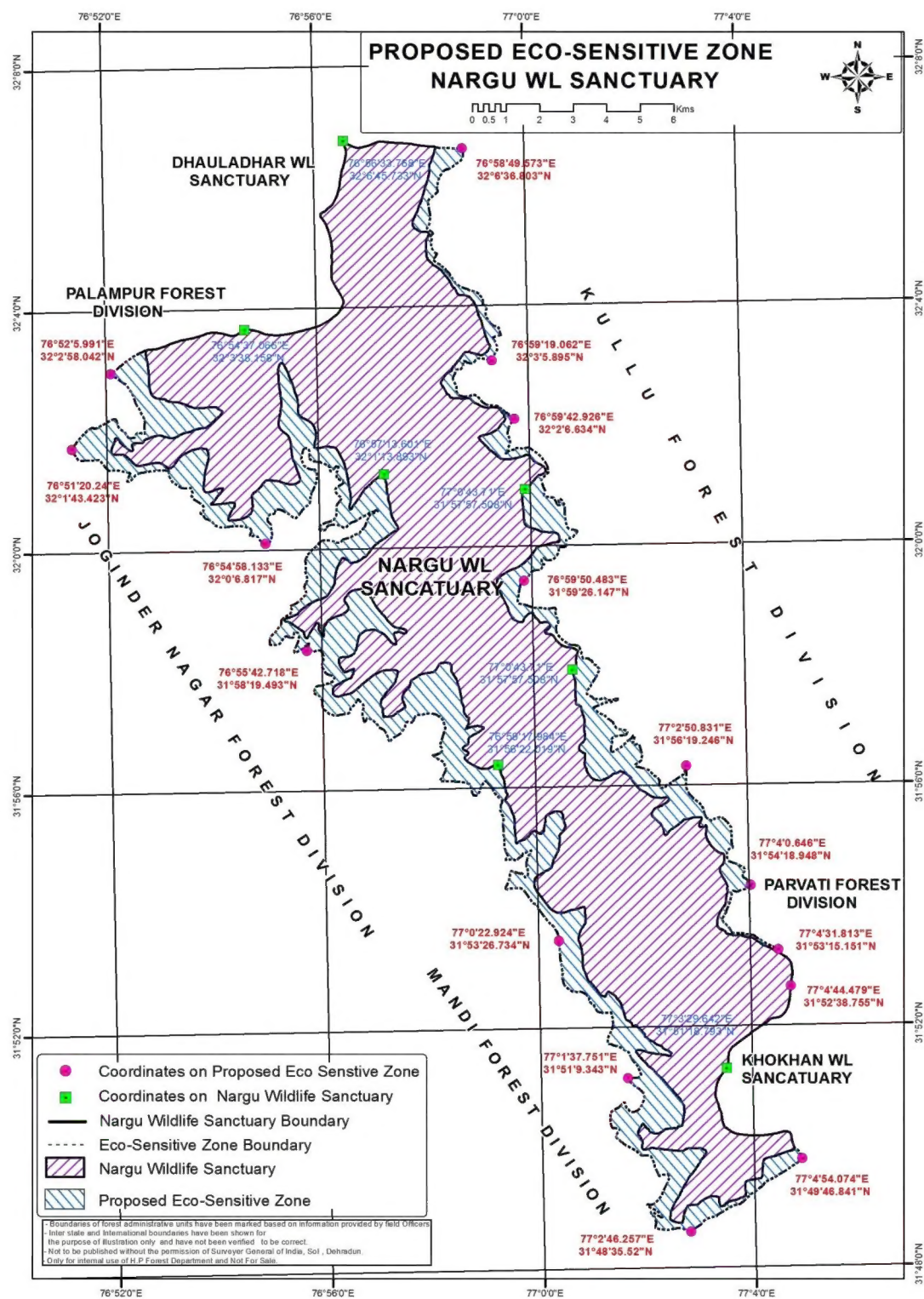
Coordinates (Easting, Northing):

- 76°52'0"E, 32°00'0"N
- 76°56'0"E, 32°00'0"N
- 77°0'0"E, 32°00'0"N
- 77°4'0"E, 32°00'0"N
- 76°52'0"E, 32°15'0"N
- 76°56'0"E, 32°15'0"N
- 77°0'0"E, 32°15'0"N
- 77°4'0"E, 32°15'0"N
- 76°52'0"E, 32°30'0"N
- 76°56'0"E, 32°30'0"N
- 77°0'0"E, 32°30'0"N
- 77°4'0"E, 32°30'0"N
- 76°52'0"E, 32°45'0"N
- 76°56'0"E, 32°45'0"N
- 77°0'0"E, 32°45'0"N
- 77°4'0"E, 32°45'0"N
- 76°52'0"E, 32°60'0"N
- 76°56'0"E, 32°60'0"N
- 77°0'0"E, 32°60'0"N
- 77°4'0"E, 32°60'0"N
- 76°52'0"E, 32°75'0"N
- 76°56'0"E, 32°75'0"N
- 77°0'0"E, 32°75'0"N
- 77°4'0"E, 32°75'0"N
- 76°52'0"E, 32°90'0"N
- 76°56'0"E, 32°90'0"N
- 77°0'0"E, 32°90'0"N
- 77°4'0"E, 32°90'0"N
- 76°52'0"E, 32°105'0"N
- 76°56'0"E, 32°105'0"N
- 77°0'0"E, 32°105'0"N
- 77°4'0"E, 32°105'0"N

Boundaries of forest administrative units have been marked based on information provided by field officers. Inter state and international boundaries have been shown for the purpose of illustration only and have not been verified to be correct. Not to be published without the permission of Surveyor General of India, Shimla. Only for internal use of H.P. Forest Department and Not For Sale.

ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY

	Longitude (E)	Latitude (N)	Description(Landmarks)
North	76° 52' 5.991" 76° 58' 49.573"	32° 02' 58.042 32° 06' 36.803	Chakrola thach to Ghralitinu Galu along Dhauladhar Wildlife Sanctuary and District boundary
South	77° 04' 54.074" 77° 02' 46.257"	31° 49' 46.841" 31° 48' 35.52"	Kandi Galu, Dulci nala, 1600 meters contour line upto Baraun nala
East	76° 58' 49.573" 76° 59' 42.926" 77° 04' 0.646" 77° 04' 54.074"	32° 06' 36.803 32° 02' 6.634 31° 54' 18.948" 31° 49' 46.841"	Contour line 2800 meters & 2600 meters, Marig, Mulganthana, then along Khokhan Wildlife Sanctuary boundary upto Kandi Galu
West	77° 02' 46.257" 77° 0' 22.924" 76° 55' 42.718" 76° 51' 20.24" 76° 52' 5.991"	31° 48' 35.52" 31° 53' 26.734" 31° 58' 19.493" 32° 01' 43.423" 32° 02' 58.042"	Baraun nala, Ser nala, Survey of India benchmark 2453, 2321, contour line 2200, 2400, 2740 1720 meters, then along district boundary of Mandi and kangra upto Chakrola thach

ANNEXURE-IV

A. LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NARGU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Division	S. No.	Village Name	Latitude	Longitude
Jogindernagar	1	Kashamal	32° 01' 517"N	76° 51' 524"E
	2	Terang	32° 58' 648"N	76° 55' 476"E
	3	Tegar	31° 58' 964"N	76° 55' 014"E
	4	Samalang	31° 58' 648"N	76° 55' 941"E
	5	Garhgaun	31° 58' 398"N	76° 55' 984"E
	6	Kungri	31° 56' 981"N	76° 57' 320"E
Parbati		Nil		
Kullu		Nil		
Mandi	1	Kot	31° 52.245"N	077° 01.438"E
	2	Padhar	31° 52.208"N	077° 01.430"E
	3	Lehri	31° 52.003"N	077° 01.577"E
	4	Kumahardu	31° 51.812"N	077° 01.370"E
	5	Mandra	31° 52.005"N	077° 01.577"E
	6	Bharari	31° 51.660"N	077° 01.625"E
	7	Badaun	31° 49.463"N	077° 01.769"E
	8	Mathiana	31° 48.445"N	077° 02.450"E
	9	Sharang	31° 48.532"N	077° 02.469"E

	10	Kundak	31 ⁰ 49.123"N	077 ⁰ 03.038"E
	11	Kandhi	31 ⁰ 49.688"N	077 ⁰ 04.863"E

**B. AREA DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NARGU WILDLIFE SANCTUARY AREA
GIVEN AS: -**

Sr. No.	Name of Forest	No. Of Compartments	Area (in sq km)
1	2/57 Pheti Mail	C-1,C-II (Part)	0.335
2	2/61 Marig	C-1-C-IV(Part)	0.565
3	Mangarh-III	(Part)	4.900
4	Choprasa-III	(Part)	1.750
5	Tarapur-III	(Part)	3.600
6	Maharaja-III	(Part)	1.10
7	Lambachak & revenue land	(Part)	3.0050
8	Terang & Richunal & revenue land		1.8125
9	Daintnal & revenue land		2.1350
10	Kungri		3.2275
11	Wangan		1.7725
12	Khaban & revenue land		0.9950
13	Graman & Kharyan		6.8750
14	Garhgaon & revenue land		3.1975
15	Kashmalshil village	(Part)	1.4300
16	Govt waste land & revenue land	(Part)	1.0600
17	Shagnal	Whole	0.8097
18	Chunchal	Whole	0.6070
19	Bara	Whole	1.1600
20	Himgarh & Revenue land	Part	0.8750
21	Badaun & Revenue land	Part	1.9050
22	Hathipur	Part	2.4755
23	Hirbannal & Revenue land		
24	Phungandhar		
25	Shagnal & Revenue land	Part	1.2528
26	Chalaudhar	Part	0.8775
27	New Mandra & Revenue land	Part	0.7725
28	Kandi & Revenue land	Part	1.5475
		G.Total	50.0425

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.